The Administrators-General (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2010

Act 18 of 2011

Keyword(s):
The Administrators-General Act, 1963

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या—216

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०/91/2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 सितम्बर, 2011

भादपद 17, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1116/79—वि—1-11-1(क)-03/10

लखनऊ, 7 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 25 अगस्त, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2011)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में महाप्रशासक अधिनियम, 1963 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

अधिनियम संख्या 45 सन् 1963 की धारा 29 का संशोधन

2-महाप्रशासक अधिनियम, 1963 की धारा 29 की उपधारा (1) में शब्द "दो लाख रुपये" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1963) की धारा 29 की उपधारा (1) में यह प्राविधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी राज्य में परिसम्पत्तियाँ छोड़कर मृत हो गया हो तथा ऐसे राज्य के महाप्रशासक का यह समाधान हो जाय कि, किसी सरकारी बचत बैंक या किसी भविष्य निधि जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध लागू होते हैं, में जमा किसी धनराशि को छोड़कर ऐसी परिसम्पत्तियाँ मृत्यु के दिनांक को कुल दो लाख रुपये के मूल्य से अधिक नहीं थी, तो वह किसी व्यक्ति को, जो जमाकर्ता से भिन्न हो व ऐसी परिसम्पत्तियों में या उसके सम्यक् प्रशासन में हितबद्ध होने का दावा करता है, राज्य में मृतक द्वारा उसमें उल्लिखित परिसम्पत्तियाँ जो कुल दो लाख रुपये मूल्य से अनधिक होंगी, को प्राप्त करने हेतु दावेदार के रूप में अधिकृत करते हुए अपने हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दो लाख रुपये की उक्त धनराशि बहुत कम है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त धनराशि को दो लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया जाय।

तदनुसार महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
के0 के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1116(2)/79-V-1-11-1(ka)03/11
Dated Lucknow, September 7, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Mahaprashasak (Uttar Pradesh Sansodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2011) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 25, 2011:-

THE ADMINISTRATORS-GENERAL (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2010

(U.P. Act no. 18 of 2011)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature Assembly]

AN

ACT

further to amend the Administrators-General Act, 1963 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Administrators-General (Uttar Pradesh Amendment), Act, 2010.

2. In section 29 of the Administrators-General Act, 1963, in sub-section (1) *for* the words "two lakhs rupees" wherever occurring the words "ten lakhs rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 29 of Act no. 45 of 1963

STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (1) of section 29 of the Administrators-General Act, 1963 (Act no. 45 of 1963) provides that whenever any person has died leaving assets within any state and the Administrators-General of such State is satisfied that such assets, excluding any sum of money deposited in a Government Savings Bank or in any provident fund to which the provisions of the Provident Funds Act, 1925, apply, did not at the date of death exceed in the whole two lakh rupees in value, he may grant to any person, claiming otherwise than as a creditor to be interested in such assets or in the due administration thereof, a certificate under his hand entitling the claimant receive the assets therein mentioned left by the deceased within the State, to a value not exceeding in the whole two lakh rupees. In view of the present economy the amount of two lakh rupees has become a meagre amount. It has, therefore been decided to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh to enhance the said amount from two lakh rupees to ten lakh rupees.

The Administrators-General (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order
K. K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 363 राजपत्र–(हि०)–2011–(886)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 98 सा० विधा०–2011–(887)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।